(d) if so, the details of award, if any, given by the Tribunal/Court in this regard; and

(e) by when the amount of award is likely to be paid?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATARAMAN: (a) In 1993 there were 1419 accidents involving UPSRTC buses.

(b) Shri T.C. Bhagat a retire Exective Officer, Rajya Sabha Secretariat, New-Delhi and his son Ravi Bhagat who were travelling in the bus sustained injuries.

(c) Yes both the injured persons had filed two separate claims before the Motor Accident Claims Tribunal, Moradabad.

(d) The claim petition filed by Shri T.C. Bhagat was settled by the Accident Claims Tribunal, Moradabad through Lok Adalat on payment of Rs. 10,000. The Claim petition filed by shri Ravi Bhagat, son of Shri T.C. Bhagat was decided by the Tribunal on 2.2.96 and a sum of Rs. 3,19.000/- alongwith 12% interest per annum from the date of petition was awarded.

(e) A cheque No. 002458 dated 7.8.1995 for Rs. 10,000/- in compliance of the award in the case of Shri T.C. Bhagat has already been deposited with the claims Tribunal, Moradabad. Against the award in the case of Shri Ravi Bhagat. UPSRTC has filed an appeal before the Hon'ble High Court alongwith a Bank Draft for Rs. 25,000/-. The Hon'ble High Court on the appeal of UPSRTC has stayed the-operation of the award provided UPSRTC Deposits Rs. 2 lakhs with the High Court by 15.7.96. Payment of the award shall be made after the dispute in the claim is finally adjudicated by the Court.

जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई कार्य

*5. **श्री अजीत जोगी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई कार्यों की पुनरीक्षा की है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इन क्षेत्रों में सिंचाई संबंधी विकास कार्य आरंभ करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं/योजनाओं को आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इन परियोजनाओं से कमान क्षेत्र की आबादी पर निर्भर करते हुए अनुसूचित जन जातियों सहित समाज के सभी वर्गों को लाभ होता है। योजना विचार-विमर्शों के दौरान सिंचाई कार्यों की समीक्षा की जा रही है।

(घ) वर्ष 1974, में योजना आयोग के निदेशों के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए आदिवासी उप-योजना शुरू की गई थी। इसमें वृहद और मध्यम सिंचाई, परियोजनाएं भी शामिल है। आदिवासी उप-योजना के तहत शामिल 17 राज्यों में से ग्यारह राज्य नामशः आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और केरल आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई विकास की योजनाएं क्रियान्वित कर रहे हैं।

(ङ) राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

निधियों का राज्यवार आबंटन

(करोड़ रुपए)

क्रम सं॰	राज्य का नाम	राज्य के लिए अनुमोदित आठवीं योजना परिव्यय	आदिवासी उप योजना के लिए अनुमोदित आठवीं योजना परिव्यय	95-96 वार्षिक (योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा अनुमोदित)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2066.78	20.00	9.40
2.	असम	86.11	55.34	20.75
3.	बिहार	1927.17	616.12	107.80
4.	गुजरात	3426.00	75.01	21.10
5.	मध्य प्रदेश	1791.29	337.05	85.23
6.	महाराष्ट्र	2391.54	227.68	59.89
7.	मणिपुर	125.00	30.07	13.30
8.	उड़ीसा	2614.33	1118.27	70.57
9.	राजस्थान	1310.08	299.52	71.60
10.	पश्चिम बंगाल	695.00*	475.22	104.75
11.	केरल	437.00	10.73	1.25
	कुल	**16870.30**	**3265.01**	**565.74**

ADB's Assistance for Maintenance of National Highways

*6. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have sought the help of Asian Development Bank (ADB) for the construction and maintenance of some National Highways;

(b) whether the upgradation and four laning of some highways projects are also being implemented with the help of ADB;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the progress of each project as on date?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) and (d) Upgradation and four laning projects of some National Highways sections are being implemented with the help of three loans from Asian Development Bank. Loanwise details are given in Statement-I, II and III.